

प्रवासी श्रमिक और शहरी आवास

यह एडिटरियल 10/01/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "A Shelter In Pandemic" लेख पर आधारित है। इसमें प्रवासी श्रमिकों के आवास संबंधी समस्याओं के संबंध में चर्चा की गई है जनिहें कोवडि-19 महामारी ने और गंभीर बना दिया है।

संदर्भ

भारत में शहरीकरण और शहरों के वसितार के साथ-साथ आधारभूत संरचना और आवास, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जैसी सेवाओं पर दबाव की वृद्धि भी हुई है। इन मूलभूत आवश्यकताओं की अनुपलब्धता के सर्वाधिक शिकार प्रवासी श्रमिक हुए हैं। कोवडि-19 महामारी ने शहरी नरिधनों/प्रवासी श्रमिकों के बदतर आवास परदृश्य को और बगिाड दिया है। ये सभी चुनौतियाँ प्रत्यक्ष रूप से एक ठोस नीतगित ढाँचे की आवश्यकता की ओर इशारा करती हैं जसि मानवाधिकारों, संपत्ति अधिकारों और सामाजिक-आर्थिक विकास के नजरिये से भी देखा जाना चाहिये। ये नीतगित पहल सतत विकास लक्ष्य (SDG) 8.8 के अनुरूप होनी चाहिये, जो सभी श्रमिकों, वशेष रूप से प्रवासियों के लिये एक सुरक्षित और नश्चिति कार्य वातावरण प्रदान करने की अपेक्षा रखता है।

शहरी आवास और प्रवासी श्रमिक

- **बेघर शहरी परिवार:** भारत की जनगणना (वर्ष 2011) से पता चलता है कि देश की शहरी आबादी 31.16% है, जहाँ लगभग 4.5 लाख परिवार बेघर हैं और कुल 17.73 लाख आबादी के पास रहने की कोई जगह नहीं है।
 - महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहाँ गंभीर आवास संकट की स्थिति है।
- **प्रवासी और शहरी आवास:** शहरी आबादी का एक बड़ा हस्सा, वशेष रूप से प्रवासी, बदहाल आश्रय की स्थिति में और अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले स्थानों में रहते हैं।
 - भारत में आधे से अधिक शहरी परिवार एक कमरे में रहते हैं, जहाँ प्रति कमरा औसतन 4.4 व्यक्तियों का नवास है।
 - छोटी इकाइयों, होटलों और घरों में काम करने वाले प्रवासियों के मामले में उनका कार्यस्थल ही उनके ठहरने का स्थान भी है।
 - ऐसे स्थान प्रायः स्वच्छ और पर्याप्त हवादार नहीं होते।
 - अधिकांश नरिमाण श्रमिक अस्थायी व्यवस्था में रहते हैं। अनयित श्रमिक पुलों के नीचे और फुटपाथ पर सोते हैं तथा प्रायः अस्वच्छ वातावरण में समूह के रूप में रहते हैं।
- श्रमिकों के आवास पर महामारी का प्रभाव: महामारी प्रेरित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण अधिकांश श्रमिक अपने अस्थायी ठकानों को छोड़ अपने घरों की ओर पलायन करने को वशिय हुए और जो बचे रहे उन्होंने भी कार्यस्थलों के बंद होने के कारण अपने आश्रय खो दिये।
 - करिये के घरों में रहने वाले प्रवासी श्रमिक सामाजिक दूरी का पालन कर सकने में सक्षम नहीं हो सके।
 - उपनगरीय क्षेत्रों में, जहाँ प्रवासी श्रमिकों की एक बड़ी संख्या का नवास था, स्थानीय आबादी ने उनके आवासों की अस्वच्छ स्थितियों का हवाला देते हुए उन पर घर खाली करने का दबाव बनाया।
 - भले ही अधिकांश राज्य सरकारों ने मकान मालिकों से दो महीने का करिया माफ करने की अपील की, लेकिन प्रवासी श्रमिकों पर करिया चुकाने का दबाव लगातार बना रहा।
- **शहरी आवास के लिये पहल:**
 - **स्मार्ट सटिज मशिन:** स्मार्ट सटिज मशिन ने भारत की 21% शहरी आबादी को कवर करते हुए 100 शहरों की पहचान की जहाँ चार चरणों में (जनवरी 2016 से शुरू) रूपांतरण कयिा जाना है।
 - स्मार्ट सटि में उपलब्ध होने वाली प्रमुख अवसंरचनाओं में उपयुक्त जलापूर्ति, सुनश्चिति बजिली आपूर्ति, स्वच्छता और वशेष रूप से गरीबों के लिये कफियती आवास शामिल हैं।
 - **अमृत मशिन:** वर्ष 2005 में शुरू कयि गए 'कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मशिन' (अमृत/AMRUT) जैसे प्रयासों का उद्देश्य शहरीकरण की प्रक्रिया को सुचारू बनाना है।
 - इसका लक्ष्य यह सुनश्चिति करना है कि प्रत्येक घर जल की सुनश्चिति आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन तक पहुँच रखता हो।
 - यह मशिन अब अपने दूसरे चरण में पहुँच गया है जहाँ लक्ष्य शहरों को जल आपूर्ति के लिये सुरक्षित बनाना और वंचितों के लिये बेहतर सुवधिाँ प्रदान करना है।
 - 'आत्मनरिभर भारत पैकेज' में परकिल्पति ARHCs: मई 2020 में सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनरिभर भारत पैकेज' में प्रवासी श्रमिकों/शहरी गरीबों के लिये कफियती करिया आवास परसिर (Affordable Rental Housing Complexes-ARHCs) का प्रावधान भी शामिल था।

- योजना यह है कि सार्वजनिक-नज्दी भागीदारी के माध्यम से शहरों में स्थिति सरकारी वित्तपोषण आवासों को ARHCs में परिवर्तित किया जाए और वभिन्न हतिधारकों को अपनी नज्दी भूमि पर ARHCs का विकास करने एवं उनका संचालन करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाए।

प्रवासियों के लिये कफियाती आवास से संबद्ध समस्याएँ

- **आवास योजनाओं का अपरभावी करियानवयन:** सरकारी आँकड़ों से पता चलता है कि स्मार्ट सटिज मशिन की 5,196 परियोजनाओं में से 49%, जिनके लिये भारत के 100 स्मार्ट सटिज में कार्य आदेश जारी किये गए थे, अब तक अपूरण हैं।
- कारियानवयन में यह कमी नवीन नीतगत उपायों की प्रभावकारिता पर प्रश्न उठाती है।
- **WASH सुवधियों का अभाव:** आंतरिक शर्मक प्रवासियों पर **अंतरराष्ट्रीय शर्म संगठन (ILO)** की वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त जल, साफ-सफाई और स्वच्छता (water, sanitation and hygiene- WASH) सुवधियों की कमी के कारण सम्मानजनक आवास के अभाव की समस्या और बढ़ गई है।
- **अपर्याप्त सार्वजनिक शौचालय:** 'स्वच्छ भारत अभियान' के माध्यम से अधिकाधिक सार्वजनिक शौचालयों की स्थापना के बावजूद प्रवासी-सघन संकुलों में उनकी उपलब्धता पर्याप्त नहीं है।
- **करिये में अचानक वृद्धि:** प्रवासी शर्मक मलनि बस्तियों में आवास पाते हैं जो प्रायः करिये में अचानक वृद्धि के अधीन होता है और उसकी पहुँच सबसे बढतर अवसंरचना और सेवाओं तक होती है।

आगे की राह

- **आवास क्षेत्र के लिये नीतनिरमाण:** आवासों की मौजूदा स्थिति राज्य और ठेकेदारों की ओर से आवास संबंधी समस्याओं के समाधान के लिये समनवति पर्याप्तों की आवश्यकता को इंगति करती है। यह अनुबंधों के मामले में अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ-साथ आवास क्षेत्र के लिये दीर्घकालिक नीतनिरमाण और वश्लेषण की माँग रखता है।
 - एक चरम स्थिति (जहाँ मकान मालिक अचानक करिये में वृद्धि कर देता हो) के बजाय राज्य ऐसी इष्टतम स्थिति सुनिश्चति करे जहाँ करिया आवासों के लिये प्रतसिपर्द्धी बाजार के आधार पर उभरे।
- **मालिक-करियेदार संघर्षों को कम करना:** सामाजिक करिया आवास के विकास के ही साथ-साथ राज्य को यह सुनिश्चति करना चाहिये कि इन स्थानों का परविहन तंत्र, शक्तिषा और स्वास्थ्य देखभाल सुवधि तक उपयुक्त पहुँच हो।
 - आंतरिक शर्म का अध्ययन करने के लिये गठित **नीतआयोग** के कार्य समूह ने सफ़िरशि की है कि सार्वजनिक क्षेत्र में करिये के आवास का वसितार रैनबसेरा आशर्यों (Dormitory Accommodation) के प्रावधान के माध्यम से कया जा सकता है।
 - यह सार्वजनिक आवास को वहनीय बनाएगा और मकान मालिकों एवं करियेदारों के बीच संघर्ष को कम करेगा।
 - अकेले कार्य-उन्मुख नीतियों ही शर्मक प्रवासियों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं।
- **छोटे और मध्यम शहरों का पुनर्विकास:** इस बात से इनकार नहीं कया जा सकता कि छोटे और मध्यम शहरों (non-megacities) में भी अपर्याप्त योजना, गैर-मापनीय आधारभूत संरचना, अवहनीय आवास और बढतर सार्वजनिक परविहन की स्थिति है।
 - सु-शहरीकरण (Good Urbanisation) सुनिश्चति करने के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि छोटे एवं मध्यम शहरों पर भी समान रूप से ध्यान केंद्रित कया जाए और इन शहरों के अपर्याप्त आवास एवं बुनयिदी सुवधियों की कमी की समस्या को संबोधित कया जाए।

अभ्यास प्रश्न: "अपर्याप्त और अवहनीय शहरी आवास की समस्या सु-शहरीकरण के मार्ग में एक प्रमुख अवरोध है।" चर्चा कीजिये।